



ए.एफ.आर.

Neutral Citation No. – 2026:AHC:22679

निर्णय सुरक्षित : 18.12.2025

निर्णय प्रदत्त : 03.02.2026

निर्णय वेबसाइट पर उपलब्ध कराया गया : 03.02.2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या—1458 वर्ष 1984

रामफल एवं अन्य

.....अपीलकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

अपीलकर्तागण के अधिवक्ता : श्री कामता प्रसाद, श्री शशांक कुमार, श्री विनोद कुमार यादव,

श्री वीरेन्द्र सिंह परमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.)

न्यायालय संख्या – 78

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु हैं और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



माननीय न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना

1. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री महेश प्रसाद यादव, श्री कामता प्रसाद और राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना गया।

2. वर्तमान आपराधिक अपील दो अपीलकर्ताओं, नामतः, सुख राम के पुत्र रामफल और बैज नाथ के पुत्र धूराम द्वारा, सीआरपीसी की धारा 374 के तहत दायर की गई है, क्योंकि उन्हें आईपीसी की धारा 395 के तहत अपराध के लिए दोषी पाया गया है जिसके लिए दोनों अभियुक्तों को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा भुगतने का निर्देश दिया गया था। आरोपी-अपीलकर्ता रामफल को आईपीसी की धारा 397 के तहत अपराध का दोषी पाया गया और उसे तीन साल की कठोर कैद की सजा सुनाई गई। आरोपी रामफल के लिए, दोनों सज़ाएँ एक साथ चलने का आदेश दिया गया। यह दोषसिद्धि और सज़ा विचारण न्यायालय (विशेष सत्र न्यायाधीश, झाँसी) द्वारा 24.04.1984 के फैसले और सज़ा के आदेश के ज़रिए दर्ज की गई थी। यह आदेश सत्र मुकदमा संख्या 43/1977 (राज्य बनाम हिंदूपात एवं अन्य) में दिया गया था, जो पुलिस स्टेशन गरौठा, ज़िला झाँसी में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 10/1975 और आपराधिक मुकदमा संख्या 11/1975 से संबंधित था। इन मामलों में आईपीसी की धारा 395, 397, 307 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत अपराध शामिल थे।

3. अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि पुलिस की एक टीम, जिसमें एचसी जयराम ए.पी., सी.ए.पी. नाथूराम, सी.ए.पी. ठाकुर प्रसाद और कॉन्स्टेबल राम किशन शामिल थे और जो थारों गाँव में डकैती सुरक्षा पहरा पर तैनात थे, उन्हें 19.01.1975 को सुबह 11:30 बजे पारा गाँव के चौकीदार हरदास से सूचना मिली कि 8-9 बदमाश झाँसी के पास पियरघाटा में आने-जाने वालों से जबरन वसूली कर रहे हैं। इस सूचना पर विश्वास करते हुए, पुलिस टीम ने थारों गाँव से कालका सिंह ठाकुर और हरजू गडरिया को साथ लिया और काकरबाई चौकी के पुलिसकर्मियों - एच.सी. 759

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



सी.पी. कृष्ण पाल, सी 456 राम अवधधर, सी 507 महावीर सिंह और सी 898 वृंदावन को भी साथ लिया। उन्होंने नेपाल सिंह को भी साथ लिया, जो उन्हें घटना स्थल पियरघाटा के रास्ते में मिला। पुलिसकर्मी घटना स्थल पर पहुँचे और देखा कि 9 लोग आने-जाने वालों से जबरन वसूली कर रहे थे। उनके पास एक राइफल, दो एसबीबीएल बंदूकें, दो देसी पिस्तौल, तीन कुल्हाड़ियाँ और एक लाठी थी। वे दो लोगों धनोरा गाँव के लखन सिंह और वन रक्षक बलदेव प्रसाद खरे की तलाशी ले रहे थे। जब पुलिस पार्टी ने उन्हें रोका, तो बदमाशों में से एक ने शोर मचाया कि पुलिस आ गई है; इस पर बदमाशों ने पुलिसकर्मियों को चुनौती दी और दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलीबारी के बाद, आरोपियों की तरफ से गोलीबारी बंद हो गई और दो आरोपी रामफल और धुरम ने आत्मसमर्पण कर दिया। बाकी आरोपी भाग निकले। यह घटना 19 जनवरी, 1975 को दोपहर 12:30 बजे हुई थी। इसके अगले दिन, 20 जनवरी, 1975 को दोपहर 12:15 बजे एफआईआर दर्ज की गई।

4. गिरफ्तारी और बरामदगी के मेमो (प्रदर्श क-1) से यह खुलासा हुआ कि दो अभियुक्त-अपीलकर्ता, नामतः धुरम पुत्र बैज नाथ और रामफल पुत्र सुख राम ने पुलिस दल के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है और उनके स्वीकारोक्ति बयानों में, ज्ञापन में सात अन्य अभियुक्तों के नाम उल्लिखित किए गए हैं, वे हिंदूपात लोधी, रामरतन, मूलचंद नाई, तिजुआ तेली, हलकुआ चमार, सुखैनिया चमार, अजुद्धी चमार हैं, जिनके बारे में कहा गया है कि वे घटना स्थल पर डकैती करते हुए उपस्थित थे। मेमो में यह भी बताया गया है कि गोटी गाँव के नंदराम यादव ने उन्हें डकैती डालने के लिए बुलाया था। रामफल की तलाशी लेने पर एक देसी 12-बोर पिस्तौल, दो ज़िंदा और पाँच खाली कारतूस के साथ-साथ लूटा गया सामान बरामद हुआ; जबकि धूराम की तलाशी लेने पर गहने और घड़ी बरामद हुए।

5. जांच के दौरान, चार आरोपियों, नामतः रामरतन, हिंदूपात लोधी, रामफल और धूराम की शिनाख्त परेड आयोजित की गई।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



6. जांच के बाद, छह आरोपियों, नामतः हिंदूपत लोधी, रामरतन, रामफल, धूराम, सुखैन्या चमार और तिजुआ तेली के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है।

7. फैसले में यह बताया गया है कि सुखैन्या चमार और तिजुआ तेली, दोनों को बरी कर दिया गया था।

8. आक्षेपित निर्णय द्वारा, अभियुक्त हिंदूपात लोधी और रामरतन को आईपीसी की धारा 395 के तहत अपराध का दोषी नहीं पाया गया और उन्हें बरी कर दिया गया। अभियुक्त रामफल को भी शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत अपराध का दोषी नहीं पाया गया। अतः, उक्त अपराध से बरी कर दिया गया।

9. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने कहा है कि एफ.आई.आर. दर्ज करने में देरी हुई है। छह में से दो आरोपियों को बरी किए जाने के बाद, बाकी बचे चार आरोपियों पर डकैती का आरोप नहीं लगाया जा सकता। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस गवाह पक्षपाती थे और उन्होंने आरोपी-अपीलकर्ताओं को झूठे मामले में फँसाया है; क्योंकि आरोपी-अपीलकर्ता एक ढाबे पर बैठकर चाय पी रहे थे, तभी कुछ पुलिसकर्मी वहाँ आए और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहा। इस बात पर आरोपी-अपीलकर्ताओं और पुलिसकर्मियों के बीच बहस हो गई, जिसके कारण पुलिसकर्मियों ने आरोपी-अपीलकर्ताओं को डकैती के झूठे मामले में फँसा दिया। आगे यह भी कहा गया है कि गोलीबारी के बावजूद, किसी को भी गोली लगने से चोट नहीं आई। हालाँकि, आरोपी रामफल को पुलिसकर्मियों ने पीटा था और वह घायल हो गया था, लेकिन उसकी चोटों को क्रॉस-फायरिंग के दौरान गलती से फिसलने या गिरने का नतीजा बताया गया। साथ ही यह भी कहा गया कि दो मुख्य गवाहों लखन सिंह और बलदेव प्रसाद खरे से न्यायालय में पूछताछ नहीं की गई; डकैती के दौरान आरोपी उनसे जबरन वसूली करते हुए देखे गए थे। विद्वान अधिवक्ता ने आईपीसी की धारा 395 के तहत अपराध के लिए पाँच से कम आरोपियों के विचारण के मामले में **राम लखन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** मामले का;

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



रिकवरी के मामले में **जकरन सिंह बनाम पंजाब राज्य²** मामले का; और आईपीसी की धारा 397 के तहत सज़ा के मामले में **दिलावर सिंह बनाम दिल्ली राज्य³** मामले का हवाला दिया है।

10. **इसके उलट**, राज्य की ओर से पेश विद्वान ए.जी.ए. का कहना है कि छह लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। न्यायिक प्रक्रिया के तहत, दो आरोपियों को आरोपमुक्त कर दिया गया और दो को बरी कर दिया गया। इसलिए, आरोपियों के खिलाफ डकैती के अपराध का मुकदमा सही ढंग से शुरू किया गया था। उनका यह भी कहना है कि आरोपी-अपीलकर्ता डकैती कर रहे थे; उन्हें आस-पास के लोगों ने पहचाना था और उनके पास से गहने और घड़ियाँ बरामद की गई थीं, जिनकी पहचान उन चीजों के मालिकों ने की थी। उन्होंने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष ने 6 गवाह पेश किए हैं: पी.डब्ल्यू.-1 जयतराम सिंह, जो शिकायतकर्ता हैं और पुलिस टीम का नेतृत्व कर रहे थे; पी.डब्ल्यू.-2 नेपाल सिंह, जो एक स्वतंत्र गवाह हैं; पी.डब्ल्यू.-3 अंगद सिंह, जो जांच अधिकारी हैं; पी.डब्ल्यू.-4 मेघराज और पी.डब्ल्यू.-5 परमेश्वरी, जिन्होंने आरोपी से बरामद अपनी चीजों की पहचान की है; और पी.डब्ल्यू.-6 कुलदीप सिंह, जो हिंदूपात की गिरफ्तारी के गवाह हैं। अभियोजन पक्ष के गवाहों ने न केवल दस्तावेजी सबूतों बरामदगी की रसीद, एफ.आई.आर., साइट प्लान, आरोपी और बरामद सामान की पहचान का रसीद को साबित किया है, बल्कि उन भौतिक सबूतों प्रदर्श क.1 से 20 को भी साबित किया है जो आरोपी-अपीलकर्ताओं से बरामद किए गए थे। इसके अलावा, यह कहा गया है कि आरोपी-अपीलकर्ताओं ने बचाव में कोई सबूत पेश नहीं किया है। इसलिए, यह अपील खारिज की जानी चाहिए।

11. इस न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।

12. इस अपील में चिंता के मुख्य बिंदु ये हैं:-

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



12.1 क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के तहत डकैती के अपराध के लिए पाँच से कम बदमाशों को दोषी ठहराया जा सकता है?

12.2 क्या अकेले आरोपी-अपीलकर्ता रामफल को भारतीय दंड संहिता की धारा 397 के तहत डकैती के दौरान मौत या गंभीर चोट पहुँचाने की कोशिश के अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, जबकि विचारण न्यायालय ने आरोपी-अपीलकर्ता रामफल को शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत अपराध से बरी कर दिया है? इसका मतलब यह है कि रामफल के पास ऐसा कोई हथियार नहीं था जिससे मौत या गंभीर चोट लग सकती थी?

12.3 क्या निचली न्यायालय ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का सही मूल्यांकन किया और दो आरोपी-अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराया, जबकि दो आरोपियों को बरी कर दिया?

13. ऊपर उठाए गए चिंता के बिंदुओं पर साथ-साथ विचार किया गया है, क्योंकि यह मामला न केवल डकैती के लिए दो आरोपी-अपीलकर्ताओं को दोषी ठहराने का है, बल्कि निचली न्यायालय द्वारा सबूतों के मूल्यांकन का भी है।

14. भारतीय दंड संहिता की धारा 391 डकैती की परिभाषा बताती है, जो नीचे दी गई है:-

“जब पाँच या उससे ज़्यादा लोग मिलकर डकैती करते हैं या करने की कोशिश करते हैं, या जब डकैती करने या करने की कोशिश करने वाले लोगों की कुल संख्या और वहाँ मौजूद रहकर उसमें मदद करने वाले लोगों की संख्या मिलाकर पाँच या उससे ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसा करने, कोशिश करने या मदद करने वाले हर व्यक्ति को ‘डकैती’ करने वाला माना जाता है।”

उपरोक्त परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 390 के अंतर्गत परिभाषित ‘लूट’ शब्द से उत्पन्न हुई है, जो यह प्रावधान करती है कि सभी लूट या तो चोरी हैं या जबरन वसूली। परिभाषा नीचे दी गई है:-

“390. लूट.—“हर लूट में या तो चोरी होती है या जबरन वसूली।”

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



चोरी कब लूट बन जाती है।—चोरी "लूट" तब मानी जाती है जब चोरी करने के मकसद से, या चोरी करते समय, या चोरी की गई संपत्ति को ले जाते या ले जाने की कोशिश करते समय, अपराधी जान-बूझकर किसी व्यक्ति की मौत, चोट या गलत तरीके से रोकने का कारण बनता है या ऐसा करने की कोशिश करता है, या उसे तुरंत मौत, चोट या गलत तरीके से रोके जाने का डर दिखाता है।

जब जबरन वसूली डकैती बन जाती है।—जबरन वसूली तब "डकैती" मानी जाती है, जब अपराधी जबरन वसूली करते समय उस व्यक्ति के सामने मौजूद हो जिसे डराया-धमकाया जा रहा है, और वह अपराधी उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को तुरंत मौत, तुरंत चोट, या तुरंत गलत तरीके से रोके जाने का डर दिखाकर जबरन वसूली करता है, और ऐसा डर दिखाकर उस व्यक्ति को उसी समय वह चीज सौंपने के लिए मजबूर करता है जिसकी जबरन वसूली की जा रही है।

स्पष्टीकरण.—अपराधी को तब उपस्थित माना जाएगा जब वह दूसरे व्यक्ति को तुरंत मौत, तुरंत चोट या तुरंत गलत तरीके से रोके जाने का डर पैदा करने के लिए काफी पास हो।”

15. अभियोजन का मामला पाँच से अधिक लुटेरों द्वारा की गई जबरन वसूली से संबंधित है। अभियोजन के अनुसार, लुटेरों की संख्या नौ थी, जिनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है।

16. आरोप है कि डकैती 19.01.1975 को दोपहर 12:30 बजे हुई, जिसका उल्लेख पी.डब्ल्यू.-1 जयतराम सिंह की प्राथमिकी यानी प्रदर्श का-2 में किया गया है।

17. प्रारंभिक जांच पी.डब्ल्यू.-3 अंगद सिंह द्वारा की गई थी, जो पहले जांच अधिकारी थे और उन्होंने घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श क-3 तैयार किया था। उन्होंने आगे की जांच नहीं की, क्योंकि जांच एस.ओ. को

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



स्थानांतरित कर दी गई थी। अभियोजन पक्ष ने उन अन्य जांच अधिकारियों को पेश नहीं किया, जिन्होंने बाद की जांच की और आरोप पत्र दाखिल किया।

18. विवादित फैसले से पता चलता है कि विचारण न्यायालय ने सुखैनिया चमार और तिजुआ तेली को बरी कर दिया था। इससे पता चलता है कि जिन आरोपियों पर मुकदमा चलना था, उनकी संख्या चार हो गई।

19. दिनांक 19.06.1981 को चार अभियुक्तों के विरुद्ध दो पृथक आरोप विरचित किए गए। अभियुक्त-अपीलार्थी रामफल पर भा.दं.सं. की धारा 395, 397 और शस्त्र अधिनियम की धारा 25(1)(a) के तहत अपराध का आरोप लगाया गया, जबकि अन्य अभियुक्त धूराम और बरी किए गए दो अभियुक्तों पर भा.दं.सं. की धारा 395 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया। इससे यह दर्शित होता है कि डकैती और डकैती के दौरान मृत्यु या गंभीर उपहति कारित करने के प्रयास का आरोप चार व्यक्तियों के विरुद्ध विरचित किया गया था।

20. **राम लखन (उपरोक्त)** के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 395 के तहत अपराध के लिए अपीलकर्ता की दोषसिद्धि के खिलाफ अपील स्वीकार करते हुए माना कि डकैती के लिए दोषी ठहराए गए अभियुक्त-अपीलकर्ता पाँच से कम थे। प्रासंगिक पैराग्राफ नीचे दोहराया गया है:-

“इस अपील में, अपील करने वाले को आईपीसी 1860 की धारा 395 के तहत दोषी ठहराया गया है और 7 साल की कठोर कैद की सजा सुनाई गई है। हमारी राय में, यह अपील एक छोटी सी बात पर सफल होनी चाहिए। प्राथमिकी से पता चलता है कि डकैती में केवल नौ लोगों ने हिस्सा लिया था अर्थात्- 1. रामरूप कुर्मी, 2. रामधूप कुर्मी, 3. रामबोध कुर्मी, 4. राम नोकर कुर्मी, 5. संपूर्ण कुर्मी, 6. रामबचन कुर्मी, 7. राम लखन कुर्मी, 8. राम उजागिर कुर्मी और 9. राम प्यारे कुर्मी। आरोप है कि इस डकैती के दौरान गहने, अनाज और अन्य सामान लूट लिया गया था। विचारण न्यायालय ने पांच लोगों को बरी कर दिया था और चार को दोषी ठहराया था। लेकिन अपील पर, उच्च

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



न्यायालय ने बाकी तीन लोगों को बरी कर दिया और मौजूदा अपीलकर्ता राम लखन को दोषी ठहराया। अभी स्थिति यह है कि प्राथमिकी में नामजद नौ लोगों में से, जिन पर डकैती में शामिल होने का आरोप था, उनमें से अब सिर्फ राम लखन ही बचा है। धारा 395 के तहत अपराध तब बनता है जब पाँच या उससे ज्यादा लोगों का समूह हो। निचली न्यायालयों के निष्कर्षों से यह साफ है कि अब सिर्फ एक व्यक्ति बचा है। इसलिए, इन हालात में अपीलकर्ता को धारा 395 के तहत अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हाई कोर्ट ने ऐसा कोई प्रत्यक्ष कार्य नहीं पाया जिससे राम लखन का मामला किसी अन्य छोटे अपराध के दायरे में आता हो। इन्हीं कारणों से, अपीलकर्ता को सुनाई गई सजा और दोषसिद्धि को रद्द किया जाता है और उसे धारा 395 के तहत लगाए गए आरोप से बरी किया जाता है। तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है। आरोपी जमानत पर है। उसके जमानत-बंध रद्द किए जाते हैं।”

21. इस मामले में, डकैती का आरोप पाँच से कम आरोपियों पर लगाया गया है। इसलिए, सिर्फ इसी आधार पर अपील मंजूर की जानी चाहिए, लेकिन पेश किए गए सबूतों पर और विचार करने की ज़रूरत है ताकि यह देखा जा सके कि क्या आरोपी-अपीलकर्ता को किसी कम गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है।

22. जहाँ तक आरोपी-अपीलकर्ता रामफल की भूमिका का सवाल है – जिस पर घातक हथियार का इस्तेमाल करके जान लेने या गंभीर चोट पहुँचाने की कोशिश का आरोप था – परीक्षण न्यायाधीश ने उसे शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत दोषी नहीं ठहराया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि शस्त्र अधिनियम के तहत आरोपी-अपीलकर्ता पर मुकदमा चलाने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से मिली मंजूरी सही नहीं थी। इसलिए, आरोपी-अपीलकर्ता रामफल को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1)(a) के तहत अपराध से बरी कर दिया गया, लेकिन सबूतों पर विचार करते समय, ट्रायल जज ने खास तौर पर यह बात कही कि आरोपी-अपीलकर्ता रामफल के पास देसी पिस्तौल थी। इस बात को पी.डब्ल्यू-1 जयतराम सिंह और पी.डब्ल्यू-2 नेपाल सिंह ने साबित किया है। नेपाल

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



सिंह एक स्वतंत्र गवाह थे, जिन्हें आरोपी-अपीलकर्ता रामफल और धूराम से बरामदगी के समय गवाह बनाया गया था। पी.डब्ल्यू-2 नेपाल सिंह को एक सार्वजनिक गवाह के तौर पर पेश किया गया है; वे सेना के पूर्व जवान हैं और पुलिस पार्टी उन्हें तब साथ ले गई थी जब वे धनोरा से पियरघाटा होते हुए कोटरा जा रहे थे, और उन्हें स्वतंत्र गवाह बनाया गया। अपनी मुख्य गवाही में, उन्होंने खास तौर पर बताया कि घटना वाले दिन सुबह 11:00 बजे वे पुलिस वालों से मिले थे। उन्होंने यह भी बताया कि रास्ते में वे दो हवलदारों, छह कांस्टेबलों, कालिका और हरजू से मिले थे। उनका कहना है कि जब वे पुलिस टीम से मिले, तो पुलिस टीम पियरघाटा में बदमाशों को गिरफ्तार करने जा रही थी और उनके कहने पर वे भी उनके साथ हो लिए। परीक्षण न्यायाधीश ने एक अहम बात पर ध्यान नहीं दिया कि पुलिस को यह जानकारी पारा गाँव के चौकीदार हरदास ने सुबह करीब 11:30 बजे दी थी कि 8-9 बदमाश पियरघाटा के पास आने-जाने वालों को लूट रहे थे। रिकवरी मेमो प्रदर्श 'ख-1', जिसे अभियोजन साक्षी-1 जयतराम सिंह ने प्रमाणित किया है, में आगाह करने का समय विशेष रूप से उल्लिखित है। अभियोजन पी.डब्ल्यू-1 जयतराम सिंह और अभियोजन पी.डब्ल्यू-2 नेपाल सिंह की जिरह से यह पता चलता है कि घटना का स्थान, जो पियरघाटा है, उस स्थान से दूरी पर स्थित है जहाँ से आगाह किया गया था। पुलिस दल को सूचना मिलने के समय और नेपाल सिंह के उनसे मिलने के समय में मेल नहीं है, जिससे पता चलता है कि नेपाल सिंह को एक गवाह के तौर पर फंसाया गया है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि पी.डब्ल्यू-2 ने जिरह के दौरान बताया कि धनोरा से कोटरा पहुँचने का एक और रास्ता है, बरमैन और प्रतापपुरा होकर और इस रास्ते में पियरघाटा नहीं पड़ता। इस बात का कोई ठोस जवाब नहीं है कि इस गवाह ने अपने घर पहुँचने के लिए लंबा रास्ता क्यों चुना।

23. अभियोजन पक्ष ने दो गवाह पेश किए हैं, यानी पी.डब्ल्यू-4 मेघराज और पी.डब्ल्यू-5 परमेश्वरी; दोनों ही छात्र हैं। उन्होंने अपने बयानों में यह भी कहा है कि घटना सुबह 11:00 बजे हुई थी, जब उनका सामान लूट

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



लिया गया था। ये वही गवाह हैं जिन्होंने आरोपी के पास से बरामद अपना सामान पहचाना है। मेघराज ने अपनी पैंट, शर्ट और मोझे पहचाने, जो आरोपी रामफल के पास से बरामद हुए थे। उसने जेल में हुई शिनाख्त परेड के दौरान आरोपी हिंदूपात और रामफल की भी पहचान की थी, लेकिन परीक्षण न्यायाधीश ने हिंदूपात को बरी कर दिया और रामफल को दोषी ठहराया। अभियोजन पक्ष के मामले में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे यह पता चले कि बरामदगी के मेमो में बताए गए पैंट, शर्ट और मोजों की पहचान कैसे की गई, जबकि पी.डब्ल्यू.-4 मेघराज ने उनकी पहचान की है। पुलिस के कागजात में कहीं भी यह नहीं बताया गया है कि कपड़ों की पहचान कैसे की गई, उनका रंग क्या था और साइज़ क्या था। इससे पता चलता है कि आरोपी-अपीलकर्ता और बरामद सामान की पहचान परेड दिखावटी थी।

24. इसके अलावा, पी.डब्ल्यू.-6 कुलदीप सिंह, जिन्हें हिंदूपात की गिरफ्तारी का गवाह बनाया गया था, वे अपने बयान से मुकर गए हैं और अपनी मौजूदगी में गिरफ्तारी होने से इनकार किया है। साथ ही, अभियोजन पक्ष ने दो मुख्य स्वतंत्र गवाहों लखन सिंह और बलदेव प्रसाद खरे को पेश नहीं किया है। इन्हें पीड़ित के तौर पर दिखाया गया था; डकैती के दौरान आरोपी ने इनकी तलाशी ली थी और पुलिस ने वहाँ पहुँचकर दोनों पीड़ितों को बचाया और आरोपी को गिरफ्तार किया था। पीड़ित लखन सिंह धनोरा गाँव के रहने वाले हैं और पीड़ित बलदेव प्रसाद खरे वन रक्षक हैं। परीक्षण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा इन दो मुख्य गवाहों को पेश न करने का कोई कारण नहीं बताया गया है। इसके अलावा, आरोपी और पुलिसकर्मियों के बीच हुई गोलीबारी में किसी भी पक्ष को गोली लगने से चोट नहीं आई।

25. जिन पीड़ितों का सामान लूटा गया, उन्हें भी कोई चोट नहीं आई।

26. यह बताना गलत नहीं होगा कि डकैती वाली जगह के साइट प्लान से पता चलता है कि सड़क के दोनों तरफ जंगल है। 9 बदमाशों में से, सिर्फ दो आरोपी-अपीलकर्ताओं ने खुद आत्मसमर्पण किया और वे बाकी बदमाशों

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



के साथ भागे नहीं; इससे आरोपी-अपीलकर्ताओं की सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दिए गए बयानों में कही गई बात में दम नज़र आता है कि वे एक होटल में चाय पी रहे थे और पुलिस वाले के साथ उनकी बहस हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें डकैती के झूठे मुकदमें में फँसा दिया गया।

27. **जितेंद्र कुमार मिश्रा उर्फ जितू बनाम मध्य प्रदेश राज्य**⁴ के मामले में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलीय न्यायालय को निचली न्यायालयों द्वारा दी गई सज़ा में दखल देने में जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर अभिलेखों पर मौजूद सबूतों से पता चलता है कि अभियोजन पक्ष आरोपी के अपराध को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, और परीक्षण न्यायालय की राय से अलग कोई तर्कसंगत नज़रिया अपनाया जा सकता है तो अपीलीय न्यायालय को आरोपी को संदेह का लाभ देने से पीछे नहीं हटना चाहिए।

28. इसलिए, अपील करने वालों को डकैती या किसी अन्य छोटे अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और उन्हें डकैती करने के दौरान मौत या गंभीर चोट पहुँचाने की कोशिश और डकैती के अपराध से बरी किया जाना चाहिए, क्योंकि विचारण न्यायालय ने सबूत गलत तरीके से पेश किए थे। इस प्रकार, अधिवेशन विचार संख्या 43/1977 (राज्य बनाम हिंदूपात और अन्य) में 24.04.1984 का दोषसिद्धि का फैसला – जो मुकदमा अपराध संख्या 10/1975 पुलिस स्टेशन गरौठा, जिला झांसी से संबंधित आईपीसी की धारा 395, 397 के तहत अपराधों के लिए था – रद्द किया जाता है।

29. अपील **स्वीकार** की जाती है। अभियुक्त-अपीलकर्ता रामफल और धुरम को आईपीसी की धारा 395, 397 के तहत अपराध से बरी किया जाता है। अपीलकर्ता जमानत पर हैं। उनके जमानत मुचलके रद्द किए जाते हैं। भौतिक साक्ष्य प्रदर्श संख्या 1 से 20 को कानून के अनुसार निपटारा किया जाएगा।

30. अभिलेख इस निर्णय की प्रति सहित तत्काल वापस प्रेषित किया जाए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(माननीय न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना)

दिनांक : 03 फ़रवरी, 2026

शिवांगी

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”